MUKUL WASNIK): (a) Government is already operating a scheme namely National Welfare Fund for Sportspersons under which sportspersons who have represented the nation in International Sports Competetions and who are in indigent circumstances can get a monthly pension upto Rs. 1500.

(b) Application in prescribed proforma for grant of pension is submitted to the Department of Youth Affairs and Sports by the sportspersons and pension is sanctioned by the General Committee entrusted with the management and administration of the fund. Payments of pension are made through cheques issued in the name of the pensioner.

(c) and (d) No such case has come to the notice of the Government. However, the outstanding cricketers in indigent circumstances if any is eligible for pension or financial assistance under the National Welfare Fund for Sportspersons.

गुजरात में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लक्ष्य

3383. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के प्रत्येक जिले में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत वर्ष गुजरात के संबंध में जिला-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी , और

(घ) गत वर्ष इन लक्ष्यों की कहां तक प्राप्ति हो पाई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना समूचे देश में चल रही है जिसमें गुजरात का प्रत्येक जिला भी शामिल है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) वर्ष 1992–93 के दौरान, 18 जिलों के 7179 शेष स्कूलों वाले 123 बलाकों को इसमें शामिल करने के लिए गुजरात सरकार को 512.41 लाख रुपए की राशि विमुक्त की गई थी । इसके साथ ही गुजरात के सभी जिलों में योजना मानदण्डों के अनुसार शामिल किए जाने वाले (12393) 100% स्कूलों को वर्ष 1992–93 के अंत तक शामिल कर लिया गया है ।

आंगनबाड़ी तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को समाप्त किया जाना

3384. **श्री राम गोपाल यादव :** क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान आंगनवाड़ी तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमोंहेतु राज्य-वार तथा योजना-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ख) क्या सरकार इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धनराशि के उपयोग से संतुष्ट है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार राष्ट्र के हित में इन योजनाओं को समाप्त करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमति वासवी र.जेश्वरी) (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न सेवाओं के विस्तरण के लिए